जे.एस. नारंग, जे. के सामने

जी.एस. संधू, लेफ्टिनेंट कर्नल, —*याचिकाकर्ता*

बनाम

भारत संघ और अन्य- प्रतिवादी

C.W.P. नं. 15418/1998
19 जुलाई, 2001

भारत का संविधान, 1950-*अनुच्छेद।* 226—*सेना नियम,* 1954—*आरएलएस* 177 *और* 180—*सेना के लिए विनियम,* 1962—*रेग।* 518—*लेफ्टिनेंट कर्नल के विरुद्ध जांच न्यायालय,—संविधान—अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का अभाव—रेग।* 518 *में प्रावधान है कि पीठासीन अधिकारी का पद अपराधी अधिकारी के पद से ऊंचा होना चाहिए और विधानसभा के अन्य सदस्य कम से कम अपराधी अधिकारी के पद के समकक्ष होने चाहिए - पीठासीन अधिकारी का रैंक लेफ्टिनेंट कर्नल और अन्य होना चाहिए। मेजर रैंक के सदस्यों की नियुक्ति - नियमन में आने वाले "जहाँ भी संभव हो" शब्द को उचित रैंक और वरिष्ठता के सदस्यों का विवरण न देने के लिए एक बहाने या हैंडल के रूप में नहीं लिया जा सकता है - याचिकाकर्ता के पीछे पर्याप्त गवाहों की जांच की गई - क्रॉस करने का अवसर - याचिकाकर्ता को नहीं दिए गए सभी गवाहों की जांच करें - अनिवार्य नियमों का उल्लंघन - अपराधी अधिकारी को दिया जाने वाला अवसर प्रभावी अवसर होना चाहिए न कि कोई तमाशा - जांच न्यायालय बुलाने के आदेश, कार्यवाही और को रद्द करते हुए रिट की अनुमति दी गई उक्त जांच न्यायालय द्वारा दर्ज की गई पूछताछ।*

हेल्ड, *कि जांच न्यायालय का गठन नियम* 177 *और विनियमन* 518 *के संचयी पढ़ने के अनुसार कानून के अनुसार नहीं किया गया है, जो एक निश्चित निष्कर्ष पर ले जाता है कि जांच न्यायालय का गठन करते समय, जहां एक का चरित्र और सैन्य प्रतिष्ठा होती है अधिकारी के एक मुद्दा होने की संभावना है, पीठासीन अधिकारी को अपराधी अधिकारी के पद से उच्च पद का होना चाहिए और जांच न्यायालय की सभा के अन्य सदस्यों को कम से कम अपराधी अधिकारी के पद के बराबर होना चाहिए। चूंकि कानून के तहत परिकल्पित संविधान का*

पालन नहीं किया गया है, इसलिए 30 जून, 1996 का संयोजक आदेश सही ढंग से पारित नहीं किया गया है। उपरोक्त के अलावा, संयोजक आदेश में निहित नियम 180 के तहत जिस प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक था, उसका भी पालन नहीं किया गया, जांच की कार्यवाही पूरी तरह से टिकाऊ नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है जहां कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया है, इस प्रकार की गई जांच एक आदेश पारित करने में परिणत हो सकती है जो अपराधी अधिकारी के चरित्र और सैन्य प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकती है और विशेष रूप से जब कमांडिंग ऑफिसर को दिया गया हो। नियम 180 के तहत की गई जांच को स्वीकार करने और अपनाने की स्वतंत्रता। नियम में अपराधी अधिकारी को पूर्ण अवसर दिए जाने की परिकल्पना की गई है और नियम 22 के तहत यह प्रदान किया गया है कि दोषी अधिकारी को किसी भी गवाह से जिरह करने और अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिलेगा। तदनुसार रक्षा. चूंकि नियम 22 को परंतुक के अधीन किया गया है जिसमें यह निहित है कि यदि नियम 180 के तहत जांच की जाती है, तो कमांडिंग ऑफिसर नियम 22 के उप-नियम (1) के तहत परिकल्पित प्रक्रिया को नहीं अपना सकता है, यह पूरी तरह से आवश्यक हो जाता है कि पूर्ण अवसर दोषी अधिकारी को गवाहों से जिरह करने का अवसर देकर उसे तदनुसार अपना बचाव स्थापित करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

(पैरा 32)

आर.एस. रंधावा, वकील,-याचिकाकर्ता की ओर से।

कमल सहगल, अधिवक्ता - भारत संघ के लिए।

निर्णय

जे.एस. नारंग, जे.

---

(1) यह निर्णय 19998 की दो रिट याचिका संख्या 12793 और 15418 का निपटान करेगा क्योंकि इन दोनों मामलों में कानून और तथ्यों के सामान्य प्रश्न शामिल हैं। तथ्य 1998 के सीडब्ल्यूपी नंबर 15418 से लिए जा रहे हैं।

(2) याचिकाकर्ता को 6 सितंबर, 1970 को भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट में सेना सेवा में नियुक्त किया गया था। अपने सेवा कैरियर के दौरान याचिकाकर्ता ने विभिन्न रैंकों पर पदोन्नति अर्जित की और याचिकाकर्ता को जिस अंतिम रैंक पर

पदोन्नत किया गया वह लेफ्टिनेंट कर्नल है और याचिकाकर्ता को उसकी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के संबंध में कभी भी अभियुक्त नहीं ठहराया गया था।

(3) अगस्त, 1995 में याचिकाकर्ता को फील्ड कैश ऑफिसर, मुख्यालय 3, इन्फैंट्री डिवीजन के रूप में तैनात किया गया था। इसके अंतर्गत स्थित सैनिक अपने वेतन आदि से संबंधित मामलों में फील्ड कैश ऑफिसर पर निर्भर होते हैं। फील्ड कैशियर का कर्तव्य सरकारी खजाने से धन निकालना और इसे इकाइयों/संरचनाओं के प्रतिनिधियों को उनकी मांग के अनुसार वितरित करना है। तदनुसार उठाया गया। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि वेतन संरचनाओं या इकाई में व्यक्तियों को वितरित नहीं किया जाता है, बल्कि मांगी गई समग्र राशि उस प्रतिनिधि को दी जाती है, जो संबंधित इकाइयों में तैनात सैन्य कर्मियों के लिए और उनकी ओर से एकत्र करने के लिए विधिवत अधिकृत है।

(4) 29 जून, 1996 को, याचिकाकर्ता अपनी ड्यूटी के सामान्य दौरान भारतीय स्टेट बैंक, लेह गया था, जिसे उपरोक्त इकाइयों/संरचनाओं को संवितरित करने के लिए राशि निकालने के लिए एक सरकारी खजाने के रूप में परिभाषित किया गया है। कुल मिलाकर, नौ इकाइयों/संरचनाओं ने तदनुसार धन निकालने के लिए अपने अनुरोध प्रस्तुत किए थे। इकाइयों/संरचनाओं के प्रतिनिधि भी अपनी अपेक्षित राशि प्राप्त करने के लिए पहुँचे थे। ऐसे ही एक अधिकारी यानी 15 राजपूत रेजिमेंट के कैप्टन दीपक गौड़ भी 102 इन्फैंट्री ब्रिगेड की यूनिट/फॉर्मेशन के लिए धन इकट्ठा करने के लिए मौजूद थे। उसे रुपये की राशि एकत्र करनी थी। मांग के अनुसार 2,18,10,000। कैप्टन दीपक गौड़ सहित इकाइयों के प्रतिनिधियों को याचिकाकर्ता द्वारा अपेक्षित राशि निकालने के बाद बैंक परिसर से ही क्रमशः उपस्थित होने के लिए कहा गया था। याचिकाकर्ता ने कुल रु. आवश्यकताओं के अनुसार इकाइयों/संरचनाओं के विभिन्न प्रतिनिधियों को संवितरण के लिए 4,36,00,000 रु. कैप्टन दीपक गौड़ ने रुपये की धनराशि एकत्रित की। 2,18,10,000 को मांगे गए आंकड़े के साथ मिलान करने के बाद और गिनती करने पर, उक्त राशि को एक बॉक्स में रखा गया था, जिसमें उक्त राशि को परिसर से गठन के स्थान तक ले जाया जाना था। प्रक्रिया, प्रक्रिया और अभ्यास का विधिवत पालन किया गया और रुपये के मूल्यवर्ग के नोटों के बंडलों को जारी किया गया। 500 और रु. 100 को संबंधित अधिकारी द्वारा विधिवत नोट किया गया और उचित पुष्टि और सत्यापन के बाद, कुल राशि रु। 2,18,10,000 वितरित किए गए जिसके बदले में रसीद प्राप्त होने की पुष्टि की गई। यह ध्यान देना उचित होगा कि औसत के अनुसार कैप्टन दीपक गौड़ भुगतान प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे, जिसका अर्थ है कि राशि अन्य

अधिकारियों की उपस्थिति में उन्हें प्राप्त हुई थी। यह भी कहा गया है कि राशि एकत्र करने के बाद किसी भी अधिकारी को तब तक बैंक परिसर छोड़ने की अनुमति नहीं दी गई जब तक कि पूरा भुगतान अन्य अधिकारियों को तदनुसार वितरित नहीं कर दिया गया। अधिकारियों को उनकी मांग के अनुसार कुल राशि के वितरण के बाद, वे सभी अपेक्षित राशि के साथ परिसर से चले गए।

(5) शाम को लगभग 1630 बजे कैप्टन दीपक गौड़ याचिकाकर्ता के पास आए और बताया कि रुपये की राशि। कुल अपेक्षित राशि से 4,00,000 (चार लाख रुपये) कम पाए गए और इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक बिंदु पर पुन: जाँच की जानी आवश्यक हो गई। बैंक में बैंक अधिकारियों के साथ आंकड़ों का मिलान किया गया और निकासी और वितरित राशि बिल्कुल सही पाई गई और इसके अतिरिक्त अन्य इकाइयों/संस्थाओं के प्रतिनिधियों से भी यह पुष्टि करने के लिए संपर्क किया गया कि क्या किसी को कोई अतिरिक्त भुगतान प्राप्त हुआ है। उनमें से। प्राप्त उत्तर नकारात्मक था और सभी ने पुष्टि की कि उन्हें अपेक्षित राशि प्राप्त हुई है और इससे अधिक कुछ नहीं। मामला औपचारिक रूप से रिपोर्ट किया गया था, पुलिस में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसने स्पष्ट रूप से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के माध्यम से जांच को आकर्षित किया। संयोजक आदेश 30 जून, 1996 को पारित किया गया था जिसके तहत लेफ्टिनेंट कर्नल राकेश शर्मा, 3री इन्फैंट्री डिवीजन (सिग्नल रेजिमेंट) को मेजर के.एस. के साथ पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। मिन्हास और मेजर अतुल मारवाहा को कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी की सभा के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। जांच न्यायालय 30 जून, 1996 से 30 सितंबर, 1996 तक आयोजित किया गया था। चूंकि संयोजक आदेश की वैधता पर भी सवाल उठाया गया है, इसलिए संयोजक आदेश को उसकी संपूर्णता में नोट करना उचित होगा, जो इस प्रकार है: -

संयोजक आदेश:-

1. उन परिस्थितियों की जांच करने के लिए I के एक स्टाफ सी को बुलाया जाएगा जिनके तहत एफडी कैश ऑफ्र से चार लाख रुपये का सार्वजनिक धन (अग्रिम) निकाला गया। मुख्यालय 3 इंफ. प्रभाग. बीएन 29 जून, 1996 को आईसी-52632-ए द्वारा 16 राजपूत के कैप्टन दीपक गौड़ द्वारा मुख्यालय 102 इन्फ बीडीई की इकाइयों के लिए कुल राशि रु. निकालने के बाद गायब होने की सूचना दी गई थी। एफडी कैश ऑफिसर से 2,18,10,000 रु.

2. न्यायालय की संरचना इस प्रकार होगी:-

पीठासीन अधिकारी: 21सी 3 इन्फ डिविजन। रेफ्ट गाओ.

सदस्य: 1. एक मेजर को 3 इंफो डिव ऑर्ड. इकाई द्वारा विस्तृत किया जाना है|

2. एक प्रमुख विवरण, लद्दाख स्काउट्स मुख्याल, द्वारा दिया जाएगा |

3. गवाहों के साक्ष्य दर्ज करते समय सेना नियम 180 के प्रावधानों का अनुपालन किया जाएगा।

4. न्यायालय विस्तार से जांच करेगा और दोषी अधिकारियों/जेसीओ के खिलाफ खामियों के लिए जिम्मेदारियां तय करेगा।.

5. न्यायालय के लिए संदर्भ की शर्तें:-

(ए) जांच करते समय न्यायालय निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष रूप से जोर देगा

(i) बैंक में नकदी की सुरक्षा के साथ-साथ लेह से कारू तक नकदी ले जाते समय भी।

(ii) 15 राजपूत (कारू) के बैंक और पीछे के स्थान पर ऑफ्र के साथ-साथ जेसीओ द्वारा नकदी का लेखा-जोखा।

(iii) बैंक से नकदी निकालने के बाद, जहां सभी वाहन। कारू पहुंचने से पहले ही चला गया था.

(iv) कैश बॉक्स बदलने की परिस्थितियाँ।

5. C. I की कार्यवाही विधिवत पूरी की जाएगी 7 जुलाई, 1996 तक सेप्टुप्लिकेट में इस मुख्यालय में.

एसडी / -
बी.एस. मंगत, लेफ्टिनेंट. कर्नल एएजी,
के लिए कर्नल एडम.

(6) जांच न्यायालय द्वारा कार्यवाही के समापन के बावजूद, कोई आदेश पारित नहीं किया गया था और वर्ष 1998 में, याचिकाकर्ता ने लंबी कार्यवाही के कारण होने वाली पीड़ा को समाप्त करने की मांग के लिए इस न्यायालय के समक्ष 1998 का सीडब्ल्यूपी 2334 दायर किया था, जो अन्यथा था याचिकाकर्ता के खिलाफ कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं थे। याचिका 7 अगस्त, 1998 को वापस ली गई मानकर खारिज कर दी गई। इसके बाद, वर्तमान याचिकाएं इस आधार पर दायर की गईं कि पिछली याचिका वापस ली गई मानकर खारिज कर दी गई थी, उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ता की कुर्की करने का निर्देश दिया है। पालमपुर ताकि वह इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने की स्थिति में न हो और कोर्ट मार्शल के अधीन होने के आदेश को तदनुसार सूचित किया जा सके। इन्हीं आशंकाओं के आधार पर वर्तमान याचिकाएँ दायर की गई हैं और जाँच न्यायालय द्वारा उचित प्रक्रिया का अनुपालन न करने और जाँच न्यायालय की अनुचित संरचना पर भी आपत्ति जताई गई है। यह भी कहा गया है कि कानून के तहत प्रदान की गई उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, याचिकाकर्ता को कोर्ट मार्शल के अधीन करना बिल्कुल गलत होगा जो बिल्कुल गलत संकेत भेजेगा।

(7) याचिकाकर्ता ने विभिन्न आधारों पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी पर सवाल उठाए हैं, जैसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी नहीं बुलाई गई है, ऐसे में अंतर्निहित क्षेत्राधिकार की त्रुटि है; सेना के लिए विनियम 518 के घोर उल्लंघन में कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी का गठन किया गया है। उक्त विनियमन स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि पीठासीन अधिकारी वह होगा जो अपराधी अधिकारी से रैंक में वरिष्ठ होगा और अन्य सदस्य कम से कम दोषी अधिकारी के समकक्ष होंगे; याचिकाकर्ता सेना नियम 180 के तहत परिकल्पित पूर्ण अवसर दिए जाने का हकदार है, जिसमें कहा गया है कि उसे गवाहों के बयानों को जिरह के अधीन करने और दस्तावेजों की सत्यता का परीक्षण करने का अवसर दिया जाएगा। अपराधी अधिकारी के विरुद्ध प्रयोग किया गया। याचिकाकर्ता को सभी गवाहों से जिरह करने का अवसर नहीं दिया गया, उपरोक्त नियम का गंभीर गैर-अनुपालन है, यदि नियम 180 के अनुसार ऐसा कोई अवसर नहीं दिया जाता है, तो दोषी अधिकारी >अवसर का हकदार है जैसा कि इसके तहत परिकल्पित किया गया है। सेना नियमों के नियम 22 का उपनियम (1)। यह अधिकार इसके तहत दिए गए प्रावधान के अधीन है, जिसमें यह प्रावधान है कि यदि नियम 180 के तहत परिकल्पित अवसर प्रदान किया गया है, तो कमांडिंग ऑफिसर नियम 22 के उप नियम (1) के तहत परिकल्पित अवसर प्रदान नहीं कर सकता है।

(8) क्षेत्राधिकार के संबंध में, यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता लाड को अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी करने के लिए चंडीगढ़ स्थित मुख्यालय एन क्षेत्र से

संबद्ध किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि उसके सारांश के अनुसार भाग के संबंध में साक्ष्य को एक बार फिर से दर्ज किया गया था, साक्ष्य का सारांश पहले व्यक्ति में नहीं बल्कि तीसरे व्यक्ति में दर्ज किया गया था और यह अभ्यास उनसे प्राप्त सलाह पर किया गया था। न्यायिक शाखा। चूंकि अनुशासनात्मक कार्यवाही का कुछ हिस्सा चंडीगढ़ में आयोजित किया गया था, इसलिए इस न्यायालय के पास याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है और याचिकाकर्ता भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने का हकदार है: कार्यवाही न्यायालय की जांच भी इस आधार पर टिकाऊ नहीं है कि इसे पीठासीन अधिकारी द्वारा अकेले दर्ज किया गया था, न कि अन्य अधिकारियों की सभा में। इस संबंध में, आपत्ति के माध्यम से अभ्यावेदन भेजा गया था और उस गवाह से स्पष्ट प्रश्न पूछा गया था जिसे जिरह करने की अनुमति दी गई थी और जवाब में गवाह ने इस तथ्य की पुष्टि की कि उसका बयान पीठासीन अधिकारी की उपस्थिति में दर्ज किया गया था। अकेला; यह तर्क दिया जाता है कि यदि जांच न्यायालय की कार्यवाही अंतर्निहित दोष से ग्रस्त है, जो कानून के तहत टिकाऊ है, तो याचिकाकर्ता को कोर्ट मार्शल के अधीन करना उचित नहीं होगा; सेना नियम 22 के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया नियम 180 के तहत परिकल्पित की तुलना में एक अलग प्रक्रिया है। कमांडिंग ऑफिसर, जिनसे याचिकाकर्ता को कोर्ट मार्शल के अधीन आदेश पारित करने के लिए अपने विवेकपूर्ण दिमाग का उपयोग करने की उम्मीद की जाती है, को इस पर भरोसा करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। जांच न्यायालय द्वारा सामने लाए गए तथ्य/सबूत। यह आवश्यक है कि एक आदेश पारित करने के लिए जिसमें न्यायिक बाधाएं हों, इस प्रकार अधिकृत अधिकारी को स्वतंत्र रूप से अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए और जांच न्यायालय द्वारा दिए गए सबूतों का ध्यान रखना चाहिए, अधिकार क्षेत्र कमांडिंग ऑफिसर में निहित है लेकिन यह शक्ति कमजोर कर दी गई है परंतुक द्वारा जिसे उपरोक्त नियम के तहत परिकल्पित स्वतंत्र साक्ष्य प्राप्त करने के कमांडिंग ऑफिसर के अधिकार के विरुद्ध रोक के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है।

(9) प्रस्ताव की सूचना जारी की गई और सारांश साक्ष्य के अनुसरण में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई और उसके बाद उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड के अवलोकन पर याचिका स्वीकार कर ली गई।

(10) उत्तरदाताओं द्वारा लिखित बयान दाखिल किया गया है। पहले उदाहरण में इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर इस आधार पर सवाल उठाया गया है कि याचिकाकर्ता उत्तरी कमान के अधिकार क्षेत्र में लेह में सेवा कर रहा था जब कथित अपराध हुआ था और याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई का कोई कारण या उसका कोई हिस्सा जमा नहीं हुआ है। इस न्यायालय के क्षेत्रीय

अधिकार क्षेत्र के भीतर, याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और इसलिए, केवल इस आधार पर खारिज करने योग्य है। आगे कहा गया है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को कमांडिंग फॉर्मेशन द्वारा इकट्ठा किया गया है और आदेश पर कर्नल प्रशासन के सहायक एडजुटेंट जनरल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग के एक प्रमुख स्टाफ अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए हैं। कर्नल प्रशासन संभागीय मुख्यालय में तैनात कर्मियों की टुकड़ियों का कमांडिंग अधिकारी भी है। इस प्रकार, सेना नियम 177(3) के तहत परिकल्पित आवश्यकता का उचित अनुपालन किया गया है। इस प्रकार, जांच न्यायालय बुलाने का आदेश इस आधार पर प्रभावित नहीं होता है कि इसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित नहीं किया गया है। यह भी कहा गया है कि जांच अदालत ने याचिकाकर्ता सहित 16 गवाहों की जांच की और याचिकाकर्ता को अपना मामला रखने के लिए पूरा अवसर दिया गया था (यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील ने निर्देशों पर खुलासा किया) रिकॉर्ड के आधार पर कि सोलह गवाहों में से छह गवाहों को याचिकाकर्ता द्वारा जिरह करने की अनुमति दी गई थी)। याचिकाकर्ता सीधे तौर पर उस प्रक्रिया में शामिल था जिसे तथ्यान्वेषी जांच कहा जा सकता है। चूँकि उपरोक्त नियम का पर्याप्त अनुपालन किया गया है, इसलिए, उप नियम (1) के सेना नियम 22 के प्रावधान के मद्देनजर, उप-नियम (1) के तहत परिकल्पित प्रक्रिया को अपनाना कमांडिंग ऑफिसर के लिए बाध्य नहीं है।) नियम 22 का और वह याचिकाकर्ता को कोर्ट मार्शल के अधीन करने का आदेश पारित करने में राय बनाने के उद्देश्य से दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य के माध्यम से रिकॉर्ड पर लाए गए तथ्यों पर भरोसा करने का हकदार है। हालाँकि, अभी तक आदेश पारित नहीं किया गया है, ऐसे में यह कहना जल्दबाजी होगी कि कमांडिंग ऑफिसर द्वारा सही या गलत आदेश पारित किया गया है जैसा कि सेना नियमों के नियम 22 के तहत परिकल्पित है|

(11) यह माना जाता है कि याचिकाकर्ता ने 25 दिसंबर, 1996 से 15 जनवरी, 1997 तक छुट्टी प्राप्त की थी और उसके बाद 24 जनवरी, 1997 को उसे सामान्य अस्पताल, लेह में भर्ती कराया गया था और 12 फरवरी, 1997 को निम्न चिकित्सा श्रेणी में छुट्टी दे दी गई थी और उसे तीन सप्ताह की छुट्टी दी गई थी। बीमारी के लिए अवकाश। 24 फरवरी, 1997 को याचिकाकर्ता ने खुद को सैन्य अस्पताल, पटियाला में भर्ती कराया, जो उसके गृह नगर के नजदीक है और बाद में 6 मार्च, 1997 को कमांड अस्पताल, पश्चिमी कमान, चंडीमंदिर में स्थानांतरित कर दिया गया। याचिकाकर्ता को कम चिकित्सा में रखा गया था श्रेणी और चूंकि याचिकाकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित थी, इसलिए उसे सेना निर्देश 30/86 के तहत 14 ग्रेनेडियर्स, पालमपुर में संलग्न किया

गया था, जो उसके खिलाफ लंबित अनुशासनात्मक मामलों की प्रगति और अंतिम रूप देने के लिए मुख्यालय उत्तरी कमान के अधिकार क्षेत्र में है। याचिकाकर्ता को पालमपुर (हिमाचल प्रदेश) स्थित एक इकाई में स्थानांतरित करने के कुर्की आदेश को एक अलग याचिका यानी 1998 की सीडब्ल्यूपी 12973 के माध्यम से चुनौती दी गई है। उक्त याचिका मोशन बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आई थी और उसकी ओर से एक चेतावनी दी गई थी। उत्तरदाताओं को दायर किया गया था. इस प्रकार, उत्तरदाताओं को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया और अंतरिम उपाय के रूप में याचिकाकर्ता के आंदोलन के संबंध में यथास्थिति प्रदान की गई। उपरोक्त याचिका भी आदेश 7 जनवरी, 1999 के तहत स्वीकार की गई थी और 1998 के सीडब्ल्यूपी नंबर 15418 को उपरोक्त याचिका के साथ सुनने का आदेश दिया गया है। चूंकि तथ्य के सामान्य प्रश्न शामिल हैं, इसलिए दोनों याचिकाओं का निपटारा इस निर्णय द्वारा किया जा रहा है।

(12) उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने प्रथम दृष्टया क्षेत्राधिकार का प्रश्न उठाया है। यह तर्क दिया गया है कि जांच लेह में शुरू हुई थी और साक्ष्य का सारांश लेह में दर्ज किया गया है। बाद में याचिकाकर्ता को लेह के अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाद उसे पटियाला के सैन्य अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया और उसके बाद कमांड अस्पताल, चंडीमंदिर में स्थानांतरित कर दिया गया। उनकी निम्न चिकित्सा श्रेणी के कारण ही उन्हें चंडीमंदिर के कमांड अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वह भी वहीं से जुड़े हुए थे। यह स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ता को बाद में अनुशासनात्मक कार्यवाही के उद्देश्य से मुख्यालय एन क्षेत्र के रूप में जाना जाने वाले क्षेत्र से संबद्ध कर दिया गया था। यह भी स्वीकार किया गया है कि साक्ष्य के सारांश का कुछ हिस्सा चंडीगढ़ में दर्ज किया गया था। यह तर्क दिया गया है कि जांच लेह में शुरू हुई है और याचिकाकर्ता को 14 ग्रेनेडियर्स में संलग्न किया गया है और उत्तरी कमान के अधिकार क्षेत्र के भीतर एक इकाई होने के नाते, याचिकाकर्ता इस न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार को लागू करने का हकदार नहीं है। मेजर मोहन सिंह बनाम भारत संघ और अन्य, सीडब्ल्यूपी नंबर 5902 पर 21 दिसंबर, 1995 को निर्णय और गुरनाम सिंह बनाम भारत संघ (1) में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया गया है।

(13) दूसरी ओर, याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि बेशक जांच लेह में शुरू हुई थी, लेकिन साक्ष्य के सारांश का हिस्सा चंडीगढ़ में दर्ज किया गया था और याचिकाकर्ता को अनुशासन की पूर्ति के उद्देश्य से एन एरिया से जोड़ा गया

है। यह तर्क दिया गया है कि साक्ष्य का सारांश नियमों के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया के अनुसार दर्ज नहीं किया गया था और सेना की न्यायिक शाखा की राय के अनुसार सुधार करने के लिए, शायद साक्ष्य का पूरा सारांश चंडीगढ़ में तदनुसार फिर से दर्ज किया गया था। . आगे यह तर्क दिया गया है कि दर्ज किए गए साक्ष्य का पिछला सारांश रिकॉर्ड से लिया गया है क्योंकि इसे तीसरे व्यक्ति में दर्ज किया गया था, वर्तमान में गलती और नियम के उल्लंघन को सुधारने के प्रयास के साथ साक्ष्य को पहले व्यक्ति में दर्ज किया गया था। ओईएन प्रतिबद्ध होना। यह स्पष्ट नहीं है कि किन नियमों के तहत ऐसी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है और क्या साक्ष्य का सारांश दो बार दर्ज किया जा सकता है? हालाँकि, यदि सुधार स्वीकार कर लिया जाता है तो यह साक्ष्य के सारांश का हिस्सा नहीं है, लेकिन साक्ष्य के सारांश के तथ्य को चंडीगढ़ में दर्ज किया गया माना जाएगा। चूँकि कार्यवाही चंडीगढ़ में आयोजित की गई है या उसका कुछ हिस्सा आयोजित किया गया है, इस न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार को लागू करने के उद्देश्य से याचिकाकर्ता के पक्ष में कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ है। नवीनचंद्र एन. मजीठिया बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य (2) पर भरोसा रखा गया है। समझौते के दौरान मैंने दिनांक 11 मई, 2001 के आदेश द्वारा निर्देशित किया था, जो इस प्रकार है:-

"सुनवाई के दौरान यह पता चला है कि क्या याचिकाकर्ता को अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी करने और साक्ष्य के सारांश में कुछ संशोधन और सुधार करने के लिए मुख्यालय एन क्षेत्र से जोड़ा गया है और किसी भी संचार के अनुसरण में उक्त अभ्यास किया गया था। चंडीगढ़ में सैर की गई। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने इस आशय का एक हलफनामा दायर करने और इसके समर्थन में दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर रखने के लिए समय मांगा है। उसे ऐसा करने की इजाजत है. बता दें कि हलफनामा 15 मई, 2001 को या उससे पहले उत्तरदाताओं के वकील को अग्रिम प्रति के साथ दाखिल किया जाना चाहिए। उत्तरदाताओं के वकील, यदि चाहें, तो याचिकाकर्ता के वकील को अग्रिम प्रति के साथ उसके समर्थन में दस्तावेजों के साथ कथनों का खंडन करने वाला अतिरिक्त हलफनामा दाखिल कर सकते हैं। आगे यह निर्देश दिया गया है कि याचिकाकर्ता के मामले से संबंधित रिकॉर्ड, जैसा कि प्रवेश पीठ द्वारा उल्लिखित है, भी निर्धारित तिथि पर उपलब्ध कराया जाएगा।

18 मई, 2001 तक स्थगित कर दिया गया।

(14) उपरोक्त आदेश के अनुसरण में दोनों पक्षों ने हलफनामे दायर किए हैं, दोनों हलफनामों को संचयी रूप से पढ़ने से यह तथ्य सामने आता है कि याचिकाकर्ता को सक्षम प्राधिकारी द्वारा 60 इंजीनियर रेजिमेंट से जोड़ा गया था, -

पत्र संख्या 22001/916/डीवी- 3 के तहत उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई को अंतिम रूप देने हेतु दिनांक 17 अक्टूबर, 1996। उत्तरदाताओं द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि अनुरोध किया गया था, जो दिनांक 12 अप्रैल, 1997 का है, जिसमें पश्चिमी कमान मुख्यालय से कमांड अस्पताल, चंडीगढ़ को अधिकारी को स्टेशन मुख्यालय चंडीमंदिर के बजाय मुख्यालय "एन" क्षेत्र से जोड़ने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था क्योंकि याचिकाकर्ता ऐसा कर सकता था। उनकी मेडिकल श्रेणी को देखते हुए उन्हें उस समय लेह स्थित 60 इंजीनियर रेजिमेंट में वापस नहीं भेजा जाएगा। हालाँकि, यह तर्क दिया गया है कि सिग्नल को अनुशासनात्मक उद्देश्य के लिए मुख्यालय "एन" क्षेत्र में याचिकाकर्ता के कुर्की आदेश के रूप में नहीं कहा जा सकता है और साक्ष्य का सारांश कानूनी रूप से आरोपी व्यक्ति के कमांडिंग ऑफिसर के आदेश के तहत किसी भी स्थान पर दर्ज किया जा सकता है। . यह भी तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता को उनके पत्र संख्या 22001/926/डीवी-3 दिनांक 8 अगस्त, 1998 के तहत मुख्यालय उत्तरी कमान द्वारा 14 ग्रेनेडियर्स से जोड़ा गया था, जो एक उचित कुर्की आदेश है, लेकिन उक्त कुर्की आदेश को इस न्यायालय द्वारा रोक दिया गया था। आदेश दिनांक 21 अगस्त, 1998। 18 मई, 2001 को 3 इन्फैंट्री डिवीजन सिग्नल रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल एस. खरे के हलफनामे को पढ़ने से चीजें स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाती हैं कि (i) याचिकाकर्ता पहली बार स्टेशन से जुड़ा हुआ था मुख्यालय चंडीमंदिर और उस अधिकारी को मुख्यालय एन एरिया से जोड़ने के लिए पश्चिमी कमान से अनुरोध किया गया था और बाद में ऐसे कुर्की आदेश पारित किए जाने चाहिए थे, अन्यथा मुख्यालय उत्तरी कमान द्वारा याचिकाकर्ता को 14 ग्रेनेडियर से जोड़ने का आदेश पारित नहीं किया जा सका था और माना जाता है कि सबूतों का सारांश चंडीगढ़ में दर्ज किया गया था। इस प्रकार, बाद में, चंडीगढ़ में याचिकाकर्ता के पक्ष में कार्रवाई का एक हिस्सा उत्पन्न हुआ।

(15) मैंने दलीलों और याचिका से सामने आए तथ्यों पर गहन विचार किया है और वकील की ओर से निष्पक्ष स्वीकारोक्ति है कि साक्ष्य का सारांश चंडीगढ़ में दर्ज किया गया था और याचिकाकर्ता को पूरा करने के उद्देश्य से "एन एरिया" से जोड़ा गया था। अनुशासनात्मक प्रक्रिया, इस प्रकार कार्यवाही का कुछ हिस्सा इस न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर हुआ, मेरी राय है कि याचिकाकर्ता भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने का हकदार है।

(16) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी नहीं बुलाई गई है, जैसा कि सेना नियम 177 के तहत परिकल्पित है, जिसमें यह विशेष रूप से प्रदान किया गया है कि कोर्ट ऑफ

इंक्वायरी को सैनिकों के किसी भी निकाय की कमान संभालने वाले अधिकारी द्वारा इकट्ठा किया जाएगा, चाहे वे संबंधित हों। एक या अधिक कोर के लिए. नियम को ध्यान में रखना उचित होगा जो निम्नानुसार है: -

*"177. **जांच के न्यायालय:-(1** जांच न्यायालय अधिकारियों या जूनियर कमीशन अधिकारियों या वारंट अधिकारियों या गैर-कमीशन अधिकारियों की एक सभा है, जिन्हें साक्ष्य एकत्र करने के लिए निर्देशित किया जाता है, और यदि आवश्यक हो, तो किसी भी मामले के संबंध में रिपोर्ट करने के लिए जो उन्हें भेजा जा सकता है।*

(2) अदालत में किसी भी रैंक के कई अधिकारी, या एक या अधिक अधिकारियों के साथ एक या अधिक जूनियर कमीशन अधिकारी या वारंट अधिकारी या गैर-कमीशन अधिकारी शामिल हो सकते हैं। जाँच की प्रकृति के अनुसार न्यायालय के सदस्य सेवा की किसी भी शाखा या विभाग से संबंधित हो सकते हैं।

(3) किसी भी सैन्य दल का कमांड करने वाला अधिकारी, चाहे वह एक या अधिक कोर से संबंधित हो, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन कर सकता है।"

(17) तर्क यह है कि दिनांक 30 जनवरी 1996 का आदेश, अनुलग्नक पीआई की प्रति, जिसे ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है, को सैनिकों के किसी भी निकाय के कमांडिंग अधिकारी द्वारा पारित नहीं किया गया है, ऐसे में संयोजक आदेश स्वयं टिकाऊ नहीं है और गठित जांच न्यायालय में अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का अभाव है।

(18) दूसरी ओर, प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि आदेश पर कर्नल प्रशासन के सहायक एडजुटेंट जनरल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग के एक प्रमुख स्टाफ अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए हैं और कर्नल प्रशासन भी सेना के अधिकारी कमांडिंग अधिकारी हैं। संभागीय मुख्यालय पर तैनात कार्मिक: प्रारंभिक आपत्ति संख्या 3 के माध्यम से एक विशिष्ट याचिका ली गई है जिसका याचिकाकर्ता द्वारा खंडन नहीं किया गया है।

(19) चूंकि इस दावे से इनकार नहीं किया गया है कि कर्नल प्रशासन भी डिवीजनल मुख्यालय में तैनात कर्मियों की टुकड़ियों का कमांडिंग अधिकारी है और इसके अतिरिक्त यह कहा गया है कि आदेश पर कर्नल एडमिनिस्ट्रेशन के एडजुटेंट जनरल, जो कि एक प्रमुख कर्मचारी है, द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं।

जनरल ऑफिसर कमांडिंग और सहायक एडजुटेंट जनरल को प्राधिकार का प्रतिनिधिमंडल भी निर्विवाद रहा है। इस प्रकार, यह सुरक्षित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि आदेश अनुलग्नक पीआई इस संबंध में किसी भी अनौचित्य से ग्रस्त नहीं है जैसा कि सेना नियम 177(3) के तहत परिकल्पित है, जिसका अर्थ है कि आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया है।

(20) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया है कि जांच अदालत का गठन "सेना के लिए विनियम" के विनियम 518 में निहित वैधानिक और अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन है। उपर्युक्त विनियम में यह विशेष रूप से प्रदान किया गया है कि जब किसी अधिकारी का "चरित्र" या "सैन्य प्रतिष्ठा" एक महत्वपूर्ण मुद्दा होने की संभावना हो तो जांच न्यायालय का पीठासीन अधिकारी "जहां भी संभव हो", रैंक और अन्य सदस्यों में वरिष्ठ होगा। कम से कम उस अधिकारी के रैंक के बराबर। इस विनियमन को सेना नियम के विस्तार के रूप में पढ़ा जाना चाहिए जिसके तहत जांच अदालत को इकट्ठा करने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्त विनियम पर ध्यान देना आवश्यक है जो इस प्रकार है:-

518. कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एंड स्टेशन बोर्ड्स :-

संयोजक अधिकारी जिम्मेदार है कि जांच अदालत या स्टेशन बोर्ड उन सदस्यों से बना है जिनका अनुभव और प्रशिक्षण संबंधित मामले से निपटने के लिए उनके लिए सबसे उपयुक्त है। जांच न्यायालय या स्टेशन बोर्ड का गठन करने के लिए नियुक्त कर्मियों का जांच के विषय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई व्यक्तिगत हित या भागीदारी नहीं होनी चाहिए। जांच न्यायालय में केवल अधिकारी शामिल हो सकते हैं, या एक या अधिक अधिकारी एक या अधिक जेसीओ, डब्ल्यूओ, एनसीओ के साथ, जो भी वांछनीय हो, शामिल हो सकते हैं। जब किसी अधिकारी का चरित्र या सैन्य प्रतिष्ठा एक महत्वपूर्ण मुद्दा होने की संभावना हो, तो जांच न्यायालय का पीठासीन अधिकारी, जहां भी संभव हो, रैंक में वरिष्ठ होगा और अन्य सदस्य कम से कम उस अधिकारी के रैंक के बराबर होंगे।

सेवा उपकरणों के नुकसान की जांच करते समय, एक तकनीकी अधिकारी का साक्ष्य दर्ज किया जाना चाहिए जो अनुभवी हो और

उपकरण के तकनीकी विवरण से पूरी तरह परिचित हो। स्टेशन बोर्ड में संयोजक अधिकारी द्वारा चयनित कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है। मिश्रित नागरिक और सैन्य बोर्ड के सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी भी सामान्य या विशेष निर्देश के अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी। बोर्ड द्वारा आवश्यक स्टेशनरी और फॉर्म उस इकाई द्वारा आपूर्ति की जाएगी जो इसके लिए आवेदन करती है।

(21) अनुलग्नक पी1 का अवलोकन - जिसके तहत जांच न्यायालय को इकट्ठा किया गया है, यह दर्शाता है कि पीठासीन अधिकारी को लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर नियुक्त किया गया है और अन्य सदस्य मेजर के पद के हैं। जांच न्यायालय की यह बैठक पूर्वोक्त विनियमन का पूरी तरह से उल्लंघन है और इसलिए, जांच को आगे बढ़ाने के लिए अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का अभाव है। इस संबंध में, अनुशासन और सतर्कता निदेशालय, सेना मुख्यालय द्वारा संबोधित एक संचार का संदर्भ दिया गया है। दिल्ली दिनांक 11 अगस्त, 1983, प्रतिलिपि अनुलग्नक पी2 सभी पांच कमानों के मुख्यालयों को जारी की गई। "कम से कम" और "जहाँ भी संभव हो" शब्दों के उपयोग को विशेष रूप से समझाया गया है। यह विस्तार से बताया गया है कि "कम से कम" शब्द का अर्थ है कि अदालत के सदस्य रैंक में वरिष्ठ हो सकते हैं लेकिन किसी भी मामले में उस अधिकारी से जूनियर नहीं हो सकते जिसका चरित्र और सैन्य प्रतिष्ठा शामिल है। इस प्रकार, यह नितांत आवश्यक है कि न्यायालय को इकट्ठा करने वाले अधिकारी को अपने दिमाग का प्रयोग करना चाहिए और पहले से ही यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि क्या किसी अधिकारी का चरित्र और सैन्य प्रतिष्ठा एक महत्वपूर्ण मुद्दा होने की संभावना है। शब्द "जहाँ भी संभव हो" को उचित रैंक और वरिष्ठता के सदस्यों का विवरण न देने के लिए एक निष्पादन या हैंडल के रूप में नहीं लिया जा सकता है, इन नियमों के प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए वास्तविक और सम्मोहक कारण होने चाहिए। आगे यह भी बताया गया है कि यदि किसी वरिष्ठ अधिकारी का चरित्र और सैन्य प्रतिष्ठा पहली बार कार्यवाही के दौरान मुद्दा बन जाती है, तो मामला उस अधिकारी को भेजा जाना चाहिए जिसने अदालत को इकट्ठा किया था कि क्या अदालत को जारी रखना चाहिए या नहीं इसकी कार्यवाही या नई जांच अदालत की आवश्यकता होगी। उपरोक्त संचार में यह भी देखा गया है कि विनियमन 518 का एक नियम के रूप में सख्ती से अनुपालन किया जाएगा और उपयुक्त रैंक और वरिष्ठता के अधिकारी जांच अदालत का गठन करेंगे जहां एक अधिकारी का चरित्र और सैन्य प्रतिष्ठा एक महत्वपूर्ण मुद्दा होने की संभावना है। . वर्ष 1962 में प्रख्यापित सेना के लिए विनियमों के विनियम 518 पर जो जोर

दिया गया है, उस पर ध्यान देना उचित होगा। संचार का अंश अनुलग्नक पी2 इस प्रकार है:-

xxxxxxxxxxxx

1. ऐसे उदाहरण देखने में आए हैं कि जहां न केवल किसी जांच न्यायालय के सदस्य, बल्कि उसके पीठासीन अधिकारी भी उस अधिकारी से कनिष्ठ थे, जिसके चरित्र और सैन्य प्रतिष्ठा में मामला शामिल था। भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, इस पत्र में उपरोक्त पैरा 518 के प्रावधानों को विस्तृत किया गया है।.

2. सेना 1962 के विनियमों के पैरा 518 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब किसी अधिकारी का चरित्र या सैन्य प्रतिष्ठा एक महत्वपूर्ण मुद्दा होने की संभावना है, तो जांच अदालत के पीठासीन अधिकारी, जहां भी संभव हो, रैंक और अन्य सदस्यों में वरिष्ठ होंगे। कम से कम उस अधिकारी के रैंक के बराबर। शब्द "कम से कम" का तात्पर्य है कि अदालत के सदस्य रैंक में वरिष्ठ हो सकते हैं लेकिन किसी भी मामले में उस अधिकारी से जूनियर नहीं हो सकते जिसका चरित्र और सैन्य प्रतिष्ठा शामिल है। इसलिए, अदालत को इकट्ठा करने वाले अधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने दिमाग का प्रयोग करे और पहले ही पता लगा ले कि क्या किसी अधिकारी का चरित्र और सैन्य प्रतिष्ठा एक महत्वपूर्ण मुद्दा होने की संभावना है। शब्द "जहाँ भी संभव हो" को उचित रैंक और वरिष्ठता के सदस्यों का विवरण न देने के लिए एक निष्पादन या हैंडल के रूप में नहीं लिया जा सकता है; इन विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए वास्तविक और ठोस कारण होने चाहिए।

3. जब किसी वरिष्ठ अधिकारी का चरित्र और सैन्य प्रतिष्ठा पहली बार कार्यवाही के दौरान मुद्दा बन जाती है, तो मामले को उस अधिकारी के पास भेजा जाना चाहिए जिसने व्यक्तिगत मामलों के तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने के लिए अदालत को इकट्ठा किया था, कि क्या अदालत को अपनी कार्यवाही जारी रखनी चाहिए या नए सिरे से जांच की आवश्यकता होगी। इस बात की सराहना की

जा सकती है कि जहां एक वरिष्ठ अधिकारी का चरित्र और प्रतिष्ठा शामिल है, वहां एक कनिष्ठ अधिकारी के लिए उद्देश्यपूर्ण जांच करना मुश्किल होगा।

4. ऊपर दिए गए पैरा 518 के प्रावधानों का एक नियम के रूप में सख्ती से अनुपालन किया जाएगा और उचित रैंक और वरिष्ठता के जांच अधिकारियों की अदालत में विवरण देने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा जहां एक अधिकारी के चरित्र और सैन्य प्रतिष्ठा की संभावना हो। भौतिक मुद्दा।"

(22) दूसरी ओर, प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि सेना के लिए विनियम 518, प्रकृति में निर्देशिका है और अनिवार्य नहीं है। इस प्रकार, यदि यह स्वीकार किया जाता है कि उल्लंघन किया गया है, लेकिन याचिकाकर्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है, तो जांच अदालत के अंतर्निहित क्षेत्राधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और उक्त जांच अदालत द्वारा की गई कार्यवाही को रद्द नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, विद्वान वकील का तर्क टिकाऊ नहीं है और "जहाँ भी संभव हो" शब्द का व्यापक अर्थ है और यदि अधिकारी रैंक से ऊपर है या अपराधी अधिकारी के समकक्ष रैंक उपलब्ध नहीं है तो अदालत की ऐसी सभा का संविधान उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त विनियमन के उल्लंघन के आधार पर जांच को चुनौती नहीं दी जा सकती है और उक्त जांच न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही को ख़राब नहीं किया जा सकता है।

(23) उन प्रावधानों के अवलोकन से जो नियम बनाने के लिए केंद्र सरकार को शक्तियां प्रदान करते हैं, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील के तर्क को टिकाऊ नहीं बनाते हैं। यह सेना अधिनियम, 1950 की धारा 192 के तहत निहित है जिसके तहत नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को प्रदान की गई है और अधिनियम के सभी या किसी भी उद्देश्य के लिए नियम केंद्रीय सरकार द्वारा प्रख्यापित किए जा सकते हैं, लेकिन इसका दायरा और दायरा नियम बनाने के लिए धारा 191 के तहत केंद्र सरकार को जो शक्ति प्रदान की गई है, उससे अलग होना चाहिए। नियमों और विनियमों को अधिनियम की धारा 193 के तहत विचार और प्रावधान के अनुसार राजपत्र में प्रकाशित किया जाना आवश्यक है और इसके अतिरिक्त नियमों और विनियमों को अधिनियम की धारा 193-ए के तहत प्रदान किए गए अनुसार संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। इस प्रकार, यह सुरक्षित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि इस प्रकार प्रख्यापित नियमों और विनियमों में कानून का बल है और वे निर्देशिका और निष्क्रिय नहीं रहेंगे।

हालाँकि, यदि इसका अनुपालन न करने से दोषी अधिकारी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसे प्रत्येक मामले में देखा जाना आवश्यक होगा। वर्तमान मामले में, माना जाता है कि जांच अदालत की सभा से पता चलता है कि पीठासीन अधिकारी याचिकाकर्ता के पद के बराबर रैंक का है और सभा के अन्य सदस्य स्वीकार्य रूप से निचले पद के हैं। इस प्रकार, प्रथम दृष्टया उपरोक्त विनियम के अनुसार जांच न्यायालय का गठन नहीं किया गया है। संचार प्रति अनुलग्नक पी2 जिसके माध्यम से सभी पांच आदेशों को विनियम 518 का पालन करने का निर्देश दिया गया था, मामले को स्पष्ट करता है कि जांच अदालत के गठन के समय कार्यालय द्वारा ऐसे आदेश पारित करने को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि पीठासीन अधिकारी अपराधी अधिकारी के रैंक से ऊपर के रैंक के होंगे और अन्य सदस्य कम से कम अपराधी अधिकारी के रैंक के बराबर रैंक के होंगे। ऐसी सावधानी का पालन उस समय किया जाना चाहिए जब अधिकारी का चरित्र या सैन्य प्रतिष्ठा एक महत्वपूर्ण मुद्दा होने की संभावना हो। मामले में प्रथम दृष्टया रुपये की हेराफेरी का आरोप लगाया गया है. 4 लाख रुपये गायब पाए गए और फील्ड कैश ऑफिसर के रूप में यह संबंधित अधिकारी की प्रमुख जिम्मेदारी बन गई। इस मामले में सीधे तौर पर फील्ड कैश ऑफिसर को शामिल करते हुए एक जांच आयोजित करने की आवश्यकता थी, हालांकि जांच करने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कोई आरोप नहीं पाया जा सकता है, लेकिन माना जाता है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का दायरा फील्ड कैश ऑफिसर द्वारा किए गए रैंक तक स्पष्ट होगा। इस प्रकार, यह अधिकारी पर निर्भर था, जिसे जांच अदालत के गठन के लिए सेना नियम 177 के तहत परिकल्पित आदेश पारित करना आवश्यक था, कि जांच अदालत का गठन विनियमन 518 के तहत परिकल्पित होना चाहिए। उद्देश्य और उद्देश्य स्पष्ट है जहां भी जांच के दायरे में वरिष्ठ अधिकारी से पूछताछ करने या न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता होती है, वरिष्ठ अधिकारी को दोषी अधिकारी के पद से कनिष्ठ अधिकारी द्वारा छोटा महसूस नहीं करना चाहिए। यह आशंका कि एक कनिष्ठ अधिकारी के लिए उद्देश्यपूर्ण जांच करना मुश्किल होगा, बहुत स्पष्ट है और यही कारण है कि यह विशेष रूप से प्रदान किया गया है कि पीठासीन अधिकारी को दोषी अधिकारी और न्यायालय का गठन करने वाले अन्य अधिकारियों से वरिष्ठ होना चाहिए। जांच कम से कम उस अधिकारी के रैंक के बराबर होनी चाहिए। यह तर्क कि संबंधित प्राधिकारी द्वारा संयोजक आदेश पारित करते समय, यह ज्ञात नहीं था कि किस अधिकारी को जांच न्यायालय के अधीन किया जाएगा, किसी भी योग्यता से रहित है क्योंकि यह विशेष रूप से संदर्भित किया गया है कि राशि की कमी थी रुपये की कुल राशि के बाद मनाया गया. फील्ड कैश ऑफिसर से 2,18,10,000 रुपये निकाले

गए हैं। अन्यथा भी यदि फील्ड कैश ऑफिसर के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए जांच का दायरा बढ़ाया गया था, तो जांच न्यायालय का यह कर्तव्य था कि वह मामले को जांच न्यायालय का गठन करने वाले प्राधिकारी के पास भेज दे ताकि परिवर्तन लाने के लिए अपना दिमाग लगा सके। विनियमन के साथ लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि ऐसा किया गया है क्योंकि न तो इसकी वकालत की गई है और न ही इसे रिकॉर्ड से बाहर किया गया है। इस प्रकार, यह बिना किसी संदेह के साबित हो गया है कि संयोजक आदेश विनियम 518 के पूर्ण उल्लंघन में पारित किया गया है और जिसका पालन करना आवश्यक था, संचार दिनांक 11 अगस्त, 1983, प्रतिलिपि अनुलग्नक पी2। चूंकि जांच अदालत का गठन कानून के तहत टिकाऊ नहीं है, इसलिए जांच अदालत में अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का अभाव है।

(24) यह तर्क श्री आर.एस. द्वारा दिया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील रंधावा ने कहा कि याचिकाकर्ता को पूछताछ में अपना बचाव करने का पूरा मौका नहीं दिया गया है। उनके पीछे पर्याप्त संख्या में गवाहों से पूछताछ की गई है और उक्त गवाहों से पूछताछ करने का अवसर नहीं दिया गया है। उत्तरदाताओं द्वारा दायर बयान में यह रिकॉर्ड पर आया है कि जांच न्यायालय द्वारा 16 गवाहों की जांच की गई है और मौखिक रूप से मुझे उत्तरदाताओं के विद्वान वकील द्वारा सूचित किया गया है कि उपरोक्त कुल गवाहों में से छह गवाहों की अनुमति दी गई है। जिरह की जानी है. यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को सेना नियम 180 के तहत परिकल्पित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। इसके अलावा, यह भी तर्क दिया गया है कि जांच जारी रखी गई थी और गवाहों के बयान जांच अदालत द्वारा दर्ज किए गए थे, जब जांच अदालत के अन्य सदस्यों की अनुपस्थिति में इसकी अध्यक्षता अकेले पीठासीन अधिकारी कर रहे थे, जैसे साक्ष्य की रिकॉर्डिंग को किसी नियम या विनियम द्वारा संरक्षित नहीं किया गया है। इस तथ्य को स्पष्ट रूप से अधिकारियों को बताया गया है और गवाहों से पूछताछ के सारांश में कमी/वैधता पर एक विशिष्ट प्रश्न भी पूछा गया था, जिसे चंडीगढ़ में साक्ष्य के सारांश की पुनः रिकॉर्डिंग द्वारा ठीक करने की मांग की गई थी। आगे यह तर्क दिया गया है कि जांच सेना नियम 180 के अनुसार और अनुपालन में नहीं की गई है और जांच अदालत के सदस्यों की उपस्थिति में बयान दर्ज नहीं किए गए हैं, हालांकि जांच अदालत का गठन नहीं किया गया था। कानून के अनुसार, फिर भी उक्त जांच न्यायालय द्वारा प्रक्रिया का सही ढंग से पालन नहीं किया गया। यह स्थापित कानून है कि यदि सेना नियम 180 के अनुसार और उसे आगे बढ़ाने में दोषी अधिकारी को कोई उचित अवसर नहीं दिया जाता है, तो उसके अपमान में अपनाई गई प्रक्रिया और प्रक्रिया कानून के तहत टिकाऊ नहीं है। जांच अदालत ने वैधानिक प्रावधानों का

उल्लंघन करते हुए काम किया है, इसलिए याचिकाकर्ता को कोर्ट मार्शल के अधीन करने का आदेश पारित करने के लिए कमांडिंग ऑफिसर द्वारा तदनुसार दर्ज की गई किसी भी जांच का उपयोग नहीं किया जाएगा या उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

(25) आगे यह तर्क दिया गया है कि नियम 180 को लागू करना अनिवार्य है न कि निर्देशिका। यह एक कानूनी अधिकार है जो नियम 180 के आधार पर अपराधी अधिकारी को प्रदान किया जाता है जो गवाह से जिरह करने का अधिकार प्रदान करता है। सेना नियम 22 में किए गए संशोधन के कारण ऐसा अवसर देना अनिवार्य हो जाता है, जिसमें कमांडिंग ऑफिसर को नियम 22 के उप नियम (1) के अनुसार आगे बढ़ना आवश्यक है, लेकिन परंतुक के कारण जो कहता है कि यदि नियम 180 का अनुपालन किया गया है, कमांडिंग ऑफिसर उक्त नियम के उप नियम (1) का पालन करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता है। इस बात पर कोई विचार नहीं किया गया है कि क्या अनुच्छेद 180 के तहत परिकल्पित अधिकार अपराधी अधिकारी को दिया गया है या नहीं, जबकि प्रथम दृष्टया नियम 180 का घोर उल्लंघन हुआ है। यह उत्तरदाताओं द्वारा स्वीकार किया गया तथ्य है कि 16 गवाहों से पूछताछ की गई, जिनमें से छह को जिरह की अनुमति दी गई। जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले पर भरोसा किया गया है जिसमें यह माना गया है कि सेना नियम 180 का अनुपालन अनिवार्य है और अनुपालन न करना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। लेफ्टिनेंट कर्नल पिरथी पाल सिंह बेदी बनाम भारत संघ और अन्य (3) मामले में शीर्ष न्यायालय द्वारा निर्धारित आदेश और विनायक दौलतराव मामले में जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का भी संदर्भ दिया गया है। नलवाडे बनाम कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जी.ओ.सी. मुख्यालय. 15 कोर,(4). लेफ्टिनेंट कर्नल पिरथी पाल सिंह बेदी के मामले (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर ध्यान देना उचित होगा, जिसका अंश इस प्रकार है:-

> *"…… नियम 180 करता है समर्पण सहन न करें. यह जांच न्यायालयों के लिए निर्धारित प्रक्रिया में एक चरण स्थापित करता है। नियम 180 का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि जब भी या जहां भी अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति के संबंध में किसी भी जांच में उसके चरित्र या सैन्य प्रतिष्ठा पर असर पड़ने की संभावना हो तो जांच न्यायालय स्थापित करना अनिवार्य है। नियम 180 केवल यह अनिवार्य बनाता है कि जब भी कोई जांच न्यायालय स्थापित किया जाता है और जांच न्यायालय*

द्वारा पूछताछ के दौरान किसी व्यक्ति के चरित्र या सैन्य प्रतिष्ठा पर असर पड़ने की संभावना होती है तो ऐसे व्यक्ति को भाग लेने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। जांच न्यायालय की कार्यवाही में. जांच न्यायालय अपने स्वभाव के कारण आम तौर पर किसी स्थिति या व्यक्तियों से संबंधित कुछ मुद्दों की जांच कर सकता है। जहां सामूहिक जुर्माना लगाया जाना वांछित है, जांच न्यायालय आम तौर पर यह पता लगाने के लिए कमी की जांच कर सकता है कि कितने व्यक्ति जिम्मेदार हैं। ऐसी जांच के दौरान अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति के चरित्र या सैन्य प्रतिष्ठा के प्रभावित होने की स्पष्ट संभावना हो सकती है। उनकी भागीदारी को इस विशेष दलील पर टाला नहीं जा सकता कि उस व्यक्ति के खिलाफ कोई विशेष जांच नहीं की गई थी, जिसके चरित्र या सैन्य प्रतिष्ठा पर जांच अदालत की कार्यवाही से प्रभावित होने की संभावना है, उसे पूरा अवसर दिया जाना चाहिए ताकि उसकी पीठ पर कुछ भी न किया जाए और भागीदारी के अवसर के बिना. नियम 180 केवल ऐसी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक सक्षम प्रावधान बनाता है……. "

(26) में *विनयाह दौलतराव नलवाडे* के मामले (सुप्रा) में, इसे इस प्रकार रखा गया था।

" जांच अदालत ने अपनी राय दे दी है और वह राय दिखावटी जांच पर आधारित है जिसे आर. 180 और कला के दायरे से बाहर माना जाता है। संविधान के 14. उस राय पर प्रतिवादी ने विचार किया है और वह इससे सहमत है। उनके आदेश के आधार पर, याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र तय किया गया है जिसे यहां ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है। इन सबका आधार निश्चित रूप से कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी की कार्यवाही और उसके निष्कर्ष हैं। यदि आधार हटा दिया जाता है जैसा कि इस मामले में किया गया है, तो प्रतिवादी नंबर 1 का आदेश और आरोप पत्र भी जमीन पर गिरना चाहिए क्योंकि दोनों जांच अदालत की राय पर आधारित हैं। यदि प्रतिवादी जांच न्यायालय की राय से सहमत नहीं होता तो उसके लिए जांच का निर्देश देने का कोई अवसर नहीं था। जांच न्यायालय की राय से सहमत होने के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र तय किया गया है। तो यह जांच अदालत की राय है जिस पर प्रतिवादी के बाद के आदेश और याचिकाकर्ता के खिलाफ तय किया गया आरोप पत्र आधारित है। जांच अदालत की राय के अभाव में न तो विवादित आदेश लागू होता और न ही आरोप पत्र तय किया जाता। इसलिए, जांच न्यायालय

की राय पर आधारित कोई भी बात केवल जांच न्यायालय के निष्कर्षों के अनुरूप होगी क्योंकि इसका अपना कोई स्वतंत्र मूल नहीं है। चूंकि जांच की कार्यवाही और जांच में अदालत की कार्यवाही को भी असंवैधानिक और खराब माना गया है, इसलिए प्रतिवादी का आदेश और याचिकाकर्ता के खिलाफ तय किया गया आरोप पत्र भी रद्द किया जा सकता है और हमें इसे रद्द करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है।"

(27) दूसरी ओर, प्रतिवादियों के विद्वान वकील श्री कमल सहगल ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को उचित अवसर दिया गया था क्योंकि उसे प्रभावी गवाहों से जिरह करने की अनुमति दी गई थी और कुल मिलाकर वह स्थितियों का उत्तर जानने में सक्षम था। जिस पर उसे संदेह था। बताए गए उत्तरों का उचित प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके, चाहे वह याचिकाकर्ता के खिलाफ हो या उसके पक्ष में। विचाराधीन नियम अनिवार्य नहीं है क्योंकि केवल तथ्यान्वेषी जांच की गई है और यदि प्रथम दृष्टया राय बनानी है, तो नियमों का सावधानीपूर्वक अनुपालन करना आवश्यक नहीं है। जहां तक कमांडिंग ऑफिसर का सवाल है, उसे नियमों के तहत आदेश पारित करने के लिए औपचारिक राय पर कार्य करना होगा और निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए जांच न्यायालय द्वारा की गई तथ्यान्वेषी जांच को आधार बनाना उसके विवेक पर छोड़ दिया गया है। अपराधी अधिकारी को कोर्ट मार्शल के अधीन करने या तदनुसार उसके निर्वहन की सिफारिश करने का आदेश पारित करने में। यदि वह जांच अदालत द्वारा प्राप्त तथ्यों से संतुष्ट नहीं है तो वह सेना नियमों के नियम 22 के तहत परिकल्पित के अनुसार आगे की पुष्टि के लिए कॉल कर सकता है। इस प्रकार, जांच न्यायालय द्वारा की गई जांच की स्थिति पर सवाल उठाना जल्दबाजी होगी।

(28) उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने लेफ्टिनेंट कर्नल जी.एस. ढिल्लों बनाम भारत संघ,(5) में दिए गए फैसले पर भरोसा जताया है। यह माना गया है कि विनियमन 518 अनिवार्य नहीं है और "जहाँ भी संभव हो" शब्द पर जोर दिया गया है और नियम 177 के आधार पर न्यायालय की संरचना अवैध नहीं है और इसलिए, इसे विनियमन 518 का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है। कैप्टन वीरेंद्र कुमार बनाम भारत संघ, (6) में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को प्रतिष्ठित किया गया है। मुझे डर है कि यह उनके आधिपत्य के ध्यान में नहीं लाया गया था कि नियम वैधानिक प्रावधान के आधार पर प्रख्यापित किए गए थे और इस प्रकार प्रख्यापित नियमों और विनियमों को संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक था जैसा कि अधिनियम की धारा 193-ए के तहत परिकल्पित है। और इसके अलावा सतर्कता

निदेशालय द्वारा जारी संचार, प्रतिलिपि अनुलग्नक पी2 को भी शायद उनके आधिपत्य के ध्यान में नहीं लाया गया था। ऊपर मेरी चर्चा और उन वैधानिक प्रावधानों के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए, जिनके तहत नियम और विनियम प्रख्यापित किए गए हैं और जिस तरीके से सतर्कता निदेशक द्वारा सभी पांच आदेशों का पालन करना अनिवार्य किया गया है। मैं उपरोक्त निर्णय से सम्मानपूर्वक असहमत हूं। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय के उनके आधिपत्य ने स्पष्ट रूप से देखा है कि सेना अधिनियम और उसके तहत नियम और विनियम और निर्देश उनके आधिपत्य के समक्ष मामले में अपीलकर्ता जैसे आपातकालीन आयोग के अधिकारियों सहित कमीशन अधिकारियों के भाग्य को नियंत्रित करते हैं।……..

(5) 1987 लैब आईसी 1264 (गौहाती उच्च न्यायालय)
(6) 1981 लैब आईसी 433 (एससी)

सर्वोच्च न्यायालय के उनके आधिपत्य ने उच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया कि उसके तहत जारी निर्देशों को वैधानिक दर्जा नहीं है। यह भी देखा गया है कि जारी किए गए निर्देशों ने वैधानिक दर्जा प्राप्त कर लिया है और इसलिए, अनिवार्य रूप से लागू हैं। मौजूदा मामले में संदर्भ विनियमों का है, न कि उसके तहत जारी किए गए निर्देशों का, हालांकि अनुबंध पी2 स्पष्ट निर्देश है और विनियम 518 के अनुप्रयोग को आगे बढ़ाता है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि जिन नियमों और विनियमों को प्रख्यापित किया गया है भारत सरकार ने वैधानिक प्रावधानों के आधार पर और जिन्हें वैधानिक नियमों के अनुसार संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है, अनिवार्य दर्जा प्राप्त कर लिया है।

(29) मैंने पक्षों के विद्वान वकील की संबंधित दलीलों पर गहन विचार किया है। सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी और जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या के मद्देनजर, मैं इस बात से सम्मानजनक सहमत हूं कि विचाराधीन नियम अनिवार्य है, इसलिए जांच अदालत को पूरा अवसर देना अनिवार्य है। अपराधी अधिकारी को अपने विरुद्ध गवाही देने वाले गवाहों की स्थिति और चरित्र का पता लगाने के लिए गवाहों से जिरह करनी होती है। जो आदेश कमांडिंग ऑफिसर द्वारा पारित किया जाना है वह कई शब्दों में न्यायिक आदेश नहीं हो सकता है फिर भी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अर्ध न्यायिक विवेक के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए कि दोषी अधिकारी को कोर्ट मार्शल के अधीन किया जाना चाहिए या नहीं। इस प्रकार, यह अनिवार्य है कि अपराधी अधिकारी को अपने आचरण को स्पष्ट करने के

लिए पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए, खासकर जब अधिकारी का चरित्र और सैन्य प्रतिष्ठा भौतिक रूप से प्रभावित होने की संभावना हो और मुद्दा हो। धन की कमी के तथ्य को निर्धारित करना आवश्यक है और प्रथम दृष्टया यह पता लगाना आवश्यक है कि किस स्थान पर कमी हुई है। सेना नियम 180 की भाषा के साथ-साथ सेना नियमों के नियम 22 पर भी ध्यान देना उचित होगा, जो इस प्रकार है:

180. प्रक्रिया जब अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति का चरित्र शामिल हो-

युद्धबंदी के मामले को छोड़कर, जो तब भी अनुपस्थित रहता है जब कोई जांच अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति के चरित्र या सैन्य प्रतिष्ठा को प्रभावित करती है, ऐसे व्यक्ति को पूछताछ के दौरान उपस्थित रहने और कोई भी बयान देने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। और यदि वह कोई साक्ष्य देना या देना चाहे, और किसी ऐसे गवाह से जिरह करना, जिसका साक्ष्य उसकी राय में, उसके चरित्र या सैन्य प्रतिष्ठा को प्रभावित करता हो। न्यायालय का पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार प्रभावित है और पहले से अधिसूचित नहीं है, उसे इस नियम के तहत नोटिस प्राप्त हो और वह अपने अधिकारों को पूरी तरह से समझे।

XXXX XX XXXX XXX

22. आरोप की सुनवाई: (1) अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति के खिलाफ प्रत्येक आरोप की सुनवाई कमांडिंग ऑफिसर द्वारा आरोपी की उपस्थिति में की जाएगी। अभियुक्त को अपने खिलाफ किसी भी गवाह से जिरह करने और ऐसे गवाह को बुलाने और ऐसा बयान देने की पूरी स्वतंत्रता होगी जो उसके बचाव के लिए आवश्यक हो:

बशर्ते कि जहां आरोपी के खिलाफ आरोप किसी जांच न्यायालय द्वारा जांच के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है, जिसमें उस आरोपी के संबंध में नियम 180 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है, कमांडिंग ऑफिसर उप-नियम (1) में प्रक्रिया से छूट दे सकता है।).

(2) कमांडिंग ऑफिसर उसके सामने लाए गए आरोप को खारिज कर देगा यदि, उसकी राय में, साक्ष्य यह नहीं दिखाता है कि अधिनियम के तहत कोई अपराध किया गया है, और ऐसा कर सकता है यदि, वह संतुष्ट है कि आरोप पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए साथ :

बशर्ते कि कमांडिंग ऑफिसर उस आरोप को खारिज नहीं करेगा, जिसे धारा 120 की उप-धारा (2) के तहत विचार करने से उसमें निर्दिष्ट वरिष्ठ प्राधिकारी के संदर्भ के बिना खारिज कर दिया गया है।

(3) उप-नियम (1) के अनुपालन के बाद, यदि कमांडिंग ऑफिसर की राय है कि आरोप पर आगे बढ़ना चाहिए, तो वह उचित समय के भीतर-

(ए) धारा 80 के तहत मामले का निपटान परिशिष्ट III में दिए गए तरीके के अनुसार करें: या

(बी) मामले को उचित वरिष्ठ सैन्य प्राधिकारी को संदर्भित करें; या

(सी) साक्ष्य को लिखने के उद्देश्य से मामले को स्थगित कर दें: या

(डी) यदि अभियुक्त वारंट अधिकारी के पद से नीचे है, तो सारांश कोर्ट-मार्शल द्वारा उसके मुकदमे का आदेश दें:

बशर्ते कि कमांडिंग ऑफिसर कथित अपराधी के मुकदमे के लिए जिला कोर्ट मार्शल या सक्रिय सेवा समर जनरल कोर्ट मार्शल बुलाने के लिए सशक्त अधिकारी के संदर्भ के बिना समरी कोर्ट मार्शल द्वारा सुनवाई का आदेश नहीं देगा, जब तक कि-

(ए) अपराध वह है जिसे वह उस अधिकारी के संदर्भ के बिना सारांश कोर्ट-मार्शल द्वारा विचार कर सकता है; या

(बी) उनका मानना है कि तत्काल कार्रवाई का गंभीर कारण है और अनुशासन को नुकसान पहुंचाए बिना ऐसा संदर्भ नहीं दिया जा सकता है।

(4) जहां इस नियम के उप-नियम (3) के अनुसार लिया गया साक्ष्य उस अपराध के अलावा किसी अन्य अपराध का खुलासा करता है जो जांच का

विषय था, कमांडिंग ऑफिसर साक्ष्य के आधार पर उपयुक्त आरोप तय कर सकता है इसलिए लिया गया और साथ ही मूल आरोप की जांच भी की गई।

(30) उपरोक्त प्रावधानों का अवलोकन करने से कोई भी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अपराधी अधिकारी को दिया जाने वाला अवसर प्रभावी अवसर होना चाहिए न कि कोई दिखावा। मैंने नियम 22 के असंशोधित प्रावधानों का भी अवलोकन किया है जिसमें अधिकारियों को शामिल नहीं किया गया था और न ही प्रावधान शामिल किया गया था, लेकिन बाद में संशोधन के बाद "व्यक्ति" शब्द का उपयोग किया गया और प्रावधान प्रदान किया गया ताकि प्रावधान व्यापक रूप से लागू हो सके। नियम 22 में प्रावधान प्रदान करने के माध्यम से अनुच्छेद 180 के तहत की गई जांच वैधानिक रंग प्राप्त कर लेती है क्योंकि कमांडिंग ऑफिसर को उक्त जांच पर भरोसा करने की स्वतंत्रता दी गई है और वह नियम 22 के उप नियम (1) के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया से छूट देने का हकदार है। नियम 22 के अवलोकन से पता चलता है कि आरोपी को उसके खिलाफ किसी भी गवाह से जिरह करने की पूरी आजादी दी गई है और उसे ऐसे गवाह को बुलाने और ऐसा बयान देने का अधिकार दिया गया है जो उसके बचाव के लिए आवश्यक हो सकता है। दोनों प्रावधानों में "पूर्ण अवसर" शब्दों का उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ है कि दोषी अधिकारी को व्यापक अवसर दिया जाना चाहिए। माना जाता है कि, इस मामले में याचिकाकर्ता को सभी गवाहों से जिरह करने का अवसर नहीं दिया गया है, इस प्रकार, अनुच्छेद 180 के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया का सावधानीपूर्वक पालन नहीं किया गया है।

(31) हालाँकि, मैं खुद को इस सवाल पर जाने से रोकता हूँ कि यदि जाँच न्यायालय तीसरे व्यक्ति में साक्ष्य का सारांश रिकॉर्ड करता है और पहले व्यक्ति में फिर से रिकॉर्ड करने के लिए आगे बढ़ता है और रिकॉर्ड से पिछले साक्ष्य लेता है तो इसका क्या प्रभाव होगा। चूंकि मैं यह मान रहा हूं कि नियम 180 के तहत परिकल्पित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है और मैंने ऊपर यह भी माना है कि अनिवार्य रूप से लागू विनियमन के अनुसार जांच न्यायालय का गठन नहीं किया गया है, मैं इस संबंध में रिकॉर्ड का उल्लेख करने से बचता हूं और इस मुद्दे पर कोई भी निष्कर्ष देने से इनकार। जो रिकॉर्ड संदर्भ के लिए लिया गया था, उसे तदनुसार प्रतिवादी के विद्वान वकील को लौटा दिया गया है।

(32) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मेरा मानना है कि जांच न्यायालय का गठन नियम 177 और विनियमन 518 के संचयी पढ़ने के अनुसार कानून के अनुसार नहीं किया गया है, जो एक निश्चित निष्कर्ष पर ले जाता है कि जांच न्यायालय का गठन करते समय, जहां किसी अधिकारी का चरित्र और सैन्य प्रतिष्ठा एक मुद्दा होने की संभावना है, पीठासीन अधिकारी को अपराधी अधिकारी के पद से उच्च पद का होना चाहिए और जांच न्यायालय की सभा के अन्य सदस्य कम से कम उसके समकक्ष होने चाहिए अपराधी अधिकारी का पद. चूंकि कानून के तहत परिकल्पित संविधान का पालन नहीं किया गया है, इसलिए 30 जून, 1996 के एनेक्सर पीआई के संयोजक आदेश को सही ढंग से पारित नहीं किया गया है। उपरोक्त के अलावा, संयोजक आदेश में निहित नियम 180 के तहत जिस प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक था, उसका भी पालन नहीं किया गया, जांच की कार्यवाही पूरी तरह से टिकाऊ नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है जहां कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया है, इस प्रकार की गई जांच एक आदेश पारित करने में परिणत हो सकती है जो दोषी अधिकारी के चरित्र और सैन्य प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकती है और विशेष रूप से जब कमांडिंग ऑफिसर को दिया गया हो। नियम 180 के तहत की गई जांच को स्वीकार करने और अपनाने की स्वतंत्रता। नियम में अपराधी अधिकारी को पूरा अवसर दिए जाने की परिकल्पना की गई है और नियम 22 के तहत यह प्रदान किया गया है कि दोषी अधिकारी को किसी भी गवाह से जिरह करने और अपना बचाव स्थापित करने का पूरा अवसर मिलेगा। इसलिए। चूंकि नियम 22 को परंतुक के अधीन किया गया है जिसमें यह निहित है कि यदि नियम 180 के तहत जांच की जाती है, तो कमांडिंग ऑफिसर नियम 22 के उप नियम (1) के तहत परिकल्पित प्रक्रिया को नहीं अपना सकता है, इसलिए यह बिल्कुल जरूरी हो जाता है कि पूरा अवसर दिया जाए। दोषी अधिकारी को गवाहों से जिरह करने का अवसर दिया जाना चाहिए और तदनुसार अपना बचाव स्थापित करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

(33) याचिका स्वीकार की जाती है और अनिवार्य नियमों के उल्लंघन में पारित किए गए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, कॉपी एनेक्सचर पीआई को बुलाने के आदेश को रद्द कर दिया जाता है और उक्त कोर्ट ऑफ इंक्वायरी द्वारा दर्ज की गई कार्यवाही और प्रक्रिया और पूछताछ को भी रद्द कर दिया जाता है। जांच न्यायालय के अंतर्निहित क्षेत्राधिकार की कमी और नियमों के तहत परिकल्पित प्रक्रिया का पालन नहीं करना। यह देखा गया है कि याचिका के लंबित रहने के दौरान आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी और याचिकाकर्ता की अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत पालमपुर में अटैचमेंट पर भी रोक लगा दी गई थी, परिणामस्वरूप, इस प्रक्रिया में

जो अवधि व्यतीत हुई है, उसे पढ़ा नहीं जाएगा/ याचिकाकर्ता के पक्ष में या उत्तरदाताओं के खिलाफ लिया गया। यदि उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता के खिलाफ आगे बढ़ना उचित लगता है, तो जांच न्यायालय के गठन के चरण से ही उत्तरदाताओं को कानून के अनुसार आगे बढ़ने की स्वतंत्रता होगी। यदि ऐसा आदेश पारित किया जाना है, तो इसे कार्यवाही की शुरुआत के रूप में नहीं लिया जाएगा, बल्कि यह पहले शुरू की गई कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए होगा, जिससे यह अधिनियम की धारा 122 के दायरे में नहीं आएगा। प्रतिवादी कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के लिए कुर्की का आदेश पारित करने के लिए भी स्वतंत्र होंगे। मूल्य के हिसाब से कोई आर्डर नहीं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अंकिता गुप्ता
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
बिलासपुर, यमुनानगर |